दैनिक **लोक टुडे**

RNI No. RAJHIN/2013/50649

जनता की आवाज...
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

www.loktodaynews.com

pktimesnews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk–timesofficial

PK टाइम्स

वर्षः 12 | अंकः 275 | बुधवार 22 अप्रेल, 2026 | मूल्यः 1.00 रुपए | पृष्ठः 4

रिफाइनरी अग्निकांड...

एनआईए के हाथों में जांच...

मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर लिया जायजा

अफसरों के साथ ढाई घंटे चली हाई-लेवल मीटिंग

लोकार्पण से 20 घंटे पहले आग ने बिगाडा खेल, अब लग सकती है 6 माह तक की देरी

● लोक टुडे

जयपुर। बालोतरा जिले के पचपदरा रिफाइनरी में 20 अप्रैल को हुए भीषण अग्निकांड के बाद मंगलवार को सीएम भजनलाल शर्मा वहां पहुंचे। उन्होंने ढाई घंटे तक अधिकारियों से हादसे को लेकर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने जहां आग लगी, उस जगह का भी निरीक्षण किया। सीएम के साथ कानून मंत्री मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12॰30 बजे रिफाइनरी पहुंचे थे। इससे पहले NIA और स्टेट की जांच एजेंसियां भी पहुंच गई थीं। रिफाइनरी के गेट नंबर 1 और 2 पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरह रोक है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा– अग्निकांड की कमेटी जांच कर रही है। जो भी तकनीकी खामियां रही होंगी, उसे दूर किया जाएगा। जल्द ही रिफाइनरी को शुरू किया जाएगा।

सुरक्षा मानकों और घटना के कारणों की समीक्षा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी पहुंचकर आग से प्रभावित **Crude Distillation Unit (CDU)** का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ करीब ढाई घंटे तक बैठक की, जिसमें सुरक्षा मानकों और घटना के कारणों की समीक्षा की गई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (**NIA**) की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। टीम रिफाइनरी के स्टाफ और डिजिटल डेटा की भी जांच कर रही है। शुरुआती जांच के अनुसार आग लगने का कारण हीट एक्सचेंजर सर्किट में हाइड्रोकार्बन लीकेज बताया जा रहा है।

बेस्ट टेक्नोलॉजी और इंजीनियर्स के बावजूद हादसा :

बालोतरा (पचपदरा) में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रिफाइनरी में 20 अप्रैल दोपहर 2 बजे आग लग गई थी।

रिफाइनरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उद्घाटन करने वाले थे। इस घटना के बाद उनका दौरा स्थगित हो गया। आग उसी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में लगी, जिसका ट्रायल रन पूरा होना बताया जा रहा था। इस हादसे ने न सिर्फ सेफ्टी को लेकर सवाल खडे कर दिए हैं, बल्कि राजस्थान की इकोनॉमी को बडा घाव भी दिया है। साल 2013 से लेकर अब तक 13 सालों में पहले ही रिफाइनरी की लागत 37 हजार 230 करोड़ से बढ़कर 79 हजार 459 करोड़ तक पहुंच चुकी है। एक्सपट्डर्स से बात कर जाना कि शिलान्यास से उद्घाटन तक कौन सी चुनौतियां आईं, जिसके कारण बार–बार रिफाइनरी का काम रुका। साथ ही अब इस हादसे से कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।

एनआईए खोलेगी राज, तफ्तीश के 10 संभावित एंगल

एनआईए की जांच का तरीका बेहद वैज्ञानिक और कड़ा होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि एजेंसी इन 10 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस कर सकती है।

1. **फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन:** एनआईए की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो यानी CDU-VD यूनिट के हिस्से को सील करने, मौके के अवशेषों को लैब भिजवाने और ये पता लगाने की दिशा में कर कर सकती है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आग किसी केमिकल रिएक्शन से लगी है या किसी एक्सप्लोसिव (विस्फोटक) से।
2. **डिजिटल फुटप्रिंट की जांच:** रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का सारा डेटा और सीसीटीवी फुटेज एनआईए अपने कब्जे में ले सकती है। हादसे से ठीक पहले सिस्टम में कोई बाहरी हैकिंग या छेड़छाड़ तो नहीं हुई, इस एंगल से बारीकी से जांच हो सकती है।
3. **कॉल डंप डेटा एनालिसिस:** रिफाइनरी परिसर और उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में सक्रिय मोबाइल टावरों का डंप डेटा निकाला जा सकता है। संदिग्ध कॉल और लोकेशन की ट्रेसिंग की जा सकती है।
4. **कर्मचारियों का प्रोफाइलिंग:** रिफाइनरी में कार्यरत ठेका श्रमिकों और टेक्निकल स्टाफ की पृष्ठभूमि की जांच की जा सकती है। हाल ही में भर्ती हुए या संदिग्ध व्यवहार वाले लोगों से पूछताछ संभव है।
5. **हाइड्रोकार्बन लीक या मैनुअल टेंपरिंग:** वाल्व और फ्लैंज से हुए रिसाव की जांच होना तय है जिससे ये पता चल सकेगा कि क्या ये घिसावट की वजह से था या किसी ने जानबूझकर वाल्व के साथ छेड़छाड़ की थी।
6. **इंटेलिजेंस इनपुट से मिलान:** आईबी (IB) और अन्य खुफिया एजेंसियों से मिले हालिया इनपुट का मिलान किया जा सकता है, कि क्या रिफाइनरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर गड़बड़ी की कोई आशंका पहले से थी।
7. **तकनीकी ऑडिट:** हीट एक्सचेंजर के डिजाइन और दबाव की जांच के लिए विदेशी विशेषज्ञों या राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरों की सलाह ली जा सकती है।
8. **पीएम दौरे की सुरक्षा चूक:** प्रधानमंत्री के दौरे से 24 घंटे पहले इतनी बड़ी चूक कैसे हुईड क्या सुरक्षा घेरे में कोई सुराख थाड एनआईए इसकी भी रिपोर्ट तैयार करेगी।
9. सिस्टम लॉग्स और ऑटोमेशन फेल्योर ॰ अगर आग लगी तो ऑटोमैटिक फायर सप्रेसर सिस्टम ने उसे तुरंत क्यों नहीं बुझायाड क्या सिस्टम को डिसेबल किया गया थाड
10. **विदेशी साजिश का एंगल:** चूंकि रिफाइनरी देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय साजिश या इकोनॉमिक टेररिज्म के एंगल को भी एनआईए खंगालेगी।

रिपेयरिंग और डैमेज असेसमेंट में लग सकता है समय

रिफाइनरी मामलों के जानकार सोर्सेज ने बताया कि इस रिफाइनरी को लेकर दावा किया जा रहा था कि इसमें दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट इक्यूप्मेंट्स और बेस्ट इंजीनियर्स का इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे में उद्घाटन से पहले ये हादसा बडे सवाल खडे करता है। एक्सपट्डर्स ने बताया कि फिलहाल इतनी बडी घटना को लेकर कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी ही होगी। इसके लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि ये यूनिट किस कंपनी की थीड सप्लाई किसने किया थाड क्या ये कंपनी इंजीनियर के चार्ज में थी या इसे रिफाइनरी के इंजीनियर्स ने चार्ज में ले लिया थाड टेक्निकल ऑडिट किसने किया थाड और उन एक्सपट्डर्स की क्या रिपोर्ट थी। इन सभी सवालों के जवाब आने के बाद ही इस हादसे को लेकर कुछ ठोस कहा जा सकता है। एक्सपट्डर्स का मानना है कि रिफाइनरी के दिल में ही आग लगी है तो नुकसान तो बडा ही हुआ है। रिफाइनरी की लागत लगातार बडती जा रही है, वहीं कॉमर्शियल रन समय पर स्टार्ट नहीं होने से नुकसान अलग है। हालांकि इतनी बडी रिफाइनरी में सभी यूनिट और इक्यूप्मेंट्स डबल इंश्योर्ड होते हैं। ग्लोबल सप्लायर कंपनीज की गारंटी में भी होते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट और दुबारा फेब्रिकेशन व इंस्टॉलेशन में लगने वाला टाइम प्रोडक्शन को बडा इकोनॉमिक लॉस देता है। **CDU-VDU** यूनिट से क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन शुरू होती है। साधारण शब्दों में कहें तो यहीं क्रूड से पेट्रोल, डीजल, और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं। इस आग के बाद इसकी रिपेयरिंग और इसके डैमेज असेसमेंट में 1 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर जुलाई 2026 से कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होता, तो 9 **MMTPA** क्षमता के हिसाब से मंथली रेवेन्यू 50 हजार से 80 हजार करोड़ के आसपास होने वाला था। अब हर महीने की देरी से यह संभावित रेवेन्यू लॉस होना तय है।

NIA की रडार पर डिजिटल डेटा और रिफाइनरी स्टाफः

पचपदरा रिफाइनरी में प्रधानमंत्री के लोकार्पण से ठीक पहले लगी आग की जांच के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी **NIA** मैदान में उतर चुकी है। ये एजेंसी अब कई छोटे–बडे पहलुओं पर तफ्तीश में जुट गई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थित **'HRRL** रिफाइनरी में सोमवार को लगी आग ने पूरे देश को चौंका दिया है। 21 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महा–परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे, लेकिन अब पचपदरा की धरती पर उत्सव की शहनाई की जगह जांच की सायरन गूँज रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम ने रिफाइनरी परिसर में दस्तक दी और कमान संभाल ली है।

एनआईए की एंट्री के मायने : हादसा या रणनीतिक हमला :

साधारण आग की घटनाओं की जांच स्थानीय पुलिस या दमकल विभाग करता है, लेकिन पचपदरा में एनआईए का आना इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार इसे स्ट्रैटेजिक एसेट (रणनीतिक संपत्ति) पर हमला या बड़ी साजिश मान रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश और गृह मंत्रालय की मुस्तैदी के बाद अब एनआईए उन सुरागों को तलाशेगी जो आम आंखों से ओझल हैं।

आग की घटना से गरमाई राजनीति :

पचपदरा रिफाइनरी में आग की घटना ने राज्य की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। उद्घाटन से ठीक पहले हुए इस हादसे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप–प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बालोतरा रिफाइनरी हादसे की जांच कई एजेंसियों द्वारा की जा रही है। एनआईए और फैक्ट फाइंडिंग टीम के आने से उम्मीद है कि जल्द ही घटना के कारणों का खुलासा होगा। साथ ही, सरकार सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है।

गहलोत बोले - रिफाइनरी में अग्निकांड की जांच हो, आदर्श घोटाले पर राज्य सरकार की नीयत खराब

● लोक टुडे

जयपुर। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के चर्चित 15 हजार करोड़ रुपये के आदर्श घोटाले को लेकर राज्य सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली द्वारा उठाया गया था, जिसमें बताया गया कि करीब 22 लाख निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई है। गहलोत ने आरोप लगाया कि इस मामले में एएजी शिव मंगल की फर्म एक साथ सरकार और आरोपी पक्ष दोनों की पैरवी कर रही है, जो हितों के टकराव (Conflict of Interest) का स्पष्ट मामला है। उन्होंने कहा कि जब एक ही फर्म आरोपियों और सरकार दोनों का केस लड़ रही हो, तो

पीड़ितों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी फर्म के वकील सरकार की ओर से पेश हो रहे हैं, जबकि उसी फर्म के वकील आरोपियों का बचाव कर रहे हैं। गहलोत ने यह भी दावा किया कि इस गंभीर मामले में कई जजों ने खुद को अलग कर लिया, जो इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एएजी को तुरंत हटाकर नए वकील की नियुक्ति की जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की व्यवस्था 22 लाख निवेशकों के साथ अन्याय है और न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। गहलोत ने इस प्रकरण की तुलना संजीवनी घोटाले से करते हुए कहा कि पहले भी इसी तरह के मामलों में लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है, जिससे जनता के बीच उसकी छवि प्रभावित हो रही है।

इसके अलावा भी उन्होंने रिफाइनरी में आग लगने को लेकर कहा कि पिछले कई सालों में किसी भी रिफाइनरी में आग नहीं लगी। नई रिफाइनरी में आग लगने का सुना नहीं। पुरानी में लगती रहती है।

सेफ्टी पहले चाहे समय लग जाए.. दुर्भाग्यपूर्ण है आग की जांच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री आज जारी करेंगे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किश्त

● लोक टुडे

बाडमेर। राज्य के 66 लाख से अधिक किसानों को बुधवार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के रूप में 665 करोड़ रुपये से अधिक की राशिअंतरित की जाएगी। जोधपुर के ओसियां में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा योजना की किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर भी कृषि विभाग के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 5 किश्तों के माध्यम से प्रदेश के 71 लाख से अधिक किसान परिवारों को 2726 करोड़ रुपये से अधिक की धन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में 6 किस्तों में 9583 करोड रुपये हस्तान्तरित किए गए है। राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के समस्त पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में 3000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जा रही है। राज्य में अब योजना के पात्र किसानों को 9000 रुपये प्रति वर्ष सम्मान निधि के रूप में मिल रहे हैं ।

संभागीय स्तरों पर मिलेगी प्लग एंड प्ले सुविधा, उद्योग शुरू करना हुआ आसान

● लोक टुडे

जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रीको ने 'प्लग एंड प्ले' सुविधा देने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप, रीको द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए संभागीय स्तरों एवं किशनगढ़ में प्लग एण्ड प्ले सुविधा विकसित करने के लिए भूखण्डों का चयन कर लिया है। यह अत्याधुनिक 'प्लग एंड प्ले' सुविधा रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित की जाएगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बहुत कम समय और कम लागत में अपना उद्योग प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों यथा जयपुर में सीतापुरा फेज-तृतीय, बीकानेर में करणी औद्योगिक क्षेत्र, बोरानाडा (जोधपुर) में एग्रो फूड पार्क, भरतपुर में ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ में खोड़ा, उदयपुर में आईआईडी सेन्टर कलड़वास, कोटा में एग्रो फूड पार्क-रानपुर और अजमेर में आईटी पार्क-माकडवाली औद्योगिक क्षेत्र में इन आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उक्त भूखण्डों का आवंटन ऑनलाईन ई-ऑक्शन के माध्यम से रेन्टल बेसिस पर 15 वर्षों के लिए किया जायेगा। तत्पश्चात् 10 वर्षों का विस्तार दिया जा सकेगा। उपरोक्त भूखण? के आवंटन हेतु किराये के लिए बोली शुरू करने की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर की 5% प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमीटर होगी। किराये में वार्षिक वृद्धि प्रारंभिक किराये पर 5% प्रतिवर्ष होगी। रीको द्वारा प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा (जयपुर) में फ्लेटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स (प्लग एण्ड प्ले) में रेडी टू मूव इन मॉड्यूल्स को आवंटन हेतु खोला जाकर 14 मॉड्यल्स का लाईसेंस बेसिस पर आवंटन किया जा चुका है। औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलावा (बालोतरा) में प्लग एण्ड प्ले फैक्टरी के दो शेड निर्माण हेतु दिनांक 09.10.2025 को राशि 7.10 करो? रुपये के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं और निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इसी औद्योगिक क्षेत्र में 6 अतिरिक्त प्लग एण्ड प्ले फैक्ट्री शेड के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। रीको की यह पहल न केवल उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि राज्य में निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

वसुंधरा के फर्जी लेटर मामले में 3 कांग्रेसी हिरासत में

भोपाल पुलिस ने पकड़ा, प्रभारी हरीश चौधरी बोले- रिहा नहीं किया तो कोर्ट जाएंगे

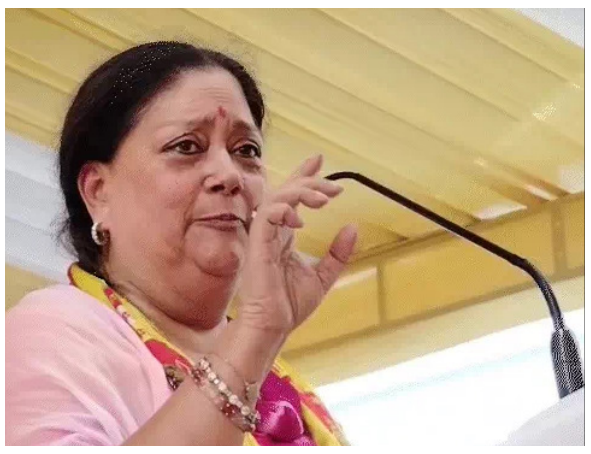

जयपुर/भोपाल। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से सोशल मीडिया पर आए फर्जी लेटर का मामला अब मध्यप्रदेश से जुड़ गया है। लेटर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर MP कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को भोपाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। एमपी के पार्टी प्रभारी हरीश चौधरी और सांसद विवेक तन्खा ने हिरासत पर सवाल उठाए हैं। हरीश चौधरी ने एक्स पर लिखा- कांग्रेस आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखना निंदनीय है। यह कानून व लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा- असहमति की आवाज दबाने का यह तरीका स्वीकार्य नहीं है। यह सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाता है। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने फेसबुक पर लिखा- पिछले 27 घंटे से भोपाल साइबर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बिना किसी वाजिब कारण के हिरासत में रखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी को टैग करते हुए कहा- एमपी पुलिस की इस कार्रवाई से उन्हें आश्चर्य और निराशा हुई है।

फर्जी पत्र बताने के बाद हिरासत में लेने पर सवाल

तन्खा ने आगे लिखा- वसुंधरा राजे की तथाकथित ट्वीट, जिसे लाखों लोगों ने देखा और साझा किया। 15-16 अप्रैल से सार्वजनिक रूप से प्रसारित हो रही थी। बाद में 18 अप्रैल को शाम लगभग 8 बजे इसे फर्जी पत्र बताया गया। ऐसे में इस आधार पर हिरासत में लेना उचित नहीं है।

श्रीसांवलियाजी के भंडार से निकले 31.1 करोड़ रुपए

चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी; अंतिम दिन होगा सोने-चांदी की भेंट का तौल

चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में श्रीसांवलिया सेठ जी मंदिर के दान भंडार की काउंटिंग का मंगलवार को चौथा राउंड पूरा हुआ। इसके बाद कुल दान राशि 31 करोड़ 1 लाख 63 हजार रुपए तक पहुंच गई हैं। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर खोले गए भंडार से इस बार भी श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि अभी अंतिम चरण की गणना बाकी है, जिसमें मंदिर को मिली सोने- चांदी की की भेंट और चिल्लर की काउंटिंग की जाती है। इससे पहले सोमवार को तीसरे चरण की गणना पूरी की गई थी। इस राउंड में 9 करोड़ 60 लाख 61 हजार 500 रुपए की राशि सामने आई। पहले और दूसरे चरण में मिलाकर 17 करोड़ 62 लाख 24 हजार 500 रुपए गिने जा चुके थे। इस तरह तीनों चरणों को जोड़ने पर कुल 27 करोड़ 22 लाख 86 हजार रुपए की राशि हो गई थी।

सत्ता सुख मिले तो भाजपा का सिद्धांतों से समझौता करने में कोई परहेज नहीं

भाजपा ने बिहार, मणिपुर, उत्तराखंड व झारखंड समेत 8 राज्यों में बनाया दूसरी विचारधारा के नेताओं को मुख्यमंत्री, बाहर से आने वाले नेताओं को मिली तरजीह

● लोक टुडे

भारतीय जनता पार्टी वैसे तो संघनिष्ठ पार्टी मानी जाती है और खुद को पक्का राष्ट्रवादी भी। जहां तक कोशिश होती है बीजेपी विचारधारा, आरएसएस से जुड़े लोगों को ही पार्टी में एंट्री के साथ तरजीह मिलती है, लेकिन स्थिति यहां कुछ अलग है। अलग अलग राज्यों में होते विधानसभा चुनाव पर जब लोक टुडे की टीम ने पडताल की तो स्थिति विचारधारा की विपरीत भी देखने को मिली। बीजेपी पूरी की पूरी विरोधी पार्टी को ही अपने में शामिल कर उनके प्रमुख नेताओं को टिकट देकर विधानसभा- लोकसभा में भेज देती है। हालांकि फिर भी बीजेपी नेताओं पर पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों को ही विधानसभा-लोकसभा सीटों में टिकट देने के आरोप लगते है, लेकिन कई बार बीजेपी ने सत्ता सुख के लिए सिद्दांतों से खुलकर समझौता किया है और अपनी सांगठनिक विचारधारा से अलग दूसरी पार्टी के नेताओं को चाहे पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत में जमकर सिद्दांतों से समझौते किए है। देश में अब तक करीब 9 प्रदेशों की कमान गैर विचारधारा से आए नेताओं को मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित किया गया है। जिससे साफ है कि उपदेश और ज्ञान केवल दूसरों को देने के लिए ही होता है जब अपने पर आती है तो समझौतावादी होने से भी बीजेपी के बड़े नेता नहीं चूकते।

पेश है विशेष रिपोर्ट...

सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे

कहते है न सत्ता के लिए कुछ भी करेगा...कैसे भी करके सत्ता मिले... इसके लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। ये बात देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी सांगठनिक विचारधारा से अलग, दूसरी पार्टियों से आए कई प्रमुख नेताओं को विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री (CM) बनाया है। इस तरह बिहार में बीजेपी ने अपना पहला मुख्यमंत्री ऐसे नेता को बनाया है, जिसका सियासी बैकग्राउंड न ही संघ का है और न ही बीजेपी का. वो जेडीए में रहे फिर बीजेपी में शामिल हुए और अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन ये अकेला पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बीजेपी ने सत्ता के लिए खुद की पार्टी के नेताओं को छोड़कर दूसरी विचारधारा के नेताओं को मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठाया है।

असम - हेमंत बिस्वा सरमा :

असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व सरमा का राजनीतिक बैकग्राउंड भी बीजेपी का नहीं रहा और न ही वह संघ की पाठशाला से आए। न ही एबीवीपी से उनका कोई लेना देना रहा, हेमंत सरमा असम में तरुण गोगोई की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 2015 में बीजेपी ज्वाइन की। 2016 के चुनाव में बीजेपी की सरकार आई तो मुख्यमंत्री बनाया गया। वे दो बार असम के मुख्यमंत्री रहे। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया था, इससे नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। मगर बीजेपी ने असम का सीएम बनाकर उन्हें उपकृत किया।

नीरज मेहरा
संपादक

मणिपुर - वीरेंद्र सिंह-खेमचंद सिंह

इसी तरह पीएम मोदी ने मणिपुर में 2017 में पहली बार सरकार बनाई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वीरेंद्र सिंह को बैठाया। वीरेंद्र सिंह का सियासी बैकग्राउंड न तो बीजेपी का था न संघ का। उनका राजनीतिक सफर डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी से शुरु हुआ था और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की मणिपुर सरकार में वीरेंद्र सिंह मंत्री रहे। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 2017 में बीजेपी की सत्ता आई तो वीरेंद्रसिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा 2022 में भी सत्ता में लौटी तो वीरेंद्र सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मणिपुर में 25 में दंगे होने के कारण होने मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। वीरेंद्र सिंह के स्थान पर यूनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। खेमचंद भी डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे।

अरुणाचल प्रदेश अपांग सीएम बने :

अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने किसी दूसरे दल से आए नेता को पहली बार सीएम ने बनाया। यहां गैंगोंग अपांग को बीजेपी की सत्ता आते ही सीएम बनाया गया। अपांग का राजनीतिक सफर कांग्रेस पार्टी से शुरु हुआ था। लेकिन वे बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की सत्ता आते ही 2023 में मुख्यमंत्री बने। फिर वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्तमान सीएम प्रेमा खांडू भी कांग्रेस में ही थे और अभी बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है।

त्रिपुरा- मानिक साहा :

त्रिपुरा के मानिक साहा कांग्रेस से आए थे। पश्चिम बंगाल से सटी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ मानिक साहा है, जिन्होंने सियासी सफर शुरु किया था कांग्रेस से। वर्ष 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा ने पहले अध्यक्ष बनाया और 2022 में मुख्यमंत्री। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिली तो सत्ता का सिंहासन फिर से मानिक साहा को सौंप दिया गया।

कर्नाटक- बसवराज बोम्मई :

कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे बसवराज बोम्मई ने जनता दल से अपनी सियासी पारी शुरु की थी। जनता दल के टुकड़े होने के बाद वे जदयू में शामिल हो गए। वर्ष 2008 में बीजेपी कर्नाटक की सत्ता में आई तो बसवराज बोम्मई ने जदयू से नाता जोड़कर तोड़कर जनता पार्टी की से जुड़ गए। भाजपा ने बैकग्राउंड को देखते हुए सीएम इस पर बैठा दिया।

झारखंड - अर्जून मुंडा :

झारखंड अर्जुन मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। 1980 के दशक में झारखंड आंदोलन के समय सक्रिय रहे। 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद भाजपा में शामिल हुए। पहली बार विधायक बने और 2003 में झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी। 2005 व 2010 में भी कमान संभाली और केंद्र में मंत्री बने।

यूपी -बृजेश पाठक :

बृजेश पाठक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में डिप्टी सीएम रहे। बृजेश पाठक ने अपनी राजनीतिक पारी कांग्रेस पार्टी से शुरू की थी। वे हरिशंकर तिवारी के करीब माने जाते थे। बहुजन समाज पार्टी में सफलता मिली और सांसद बने, फिर राज्यसभा सांसद बने। बसपा के ब्राह्मण चेहरे माने जाते थे लेकिन मायावती जब सत्ता से बाहर हो गई तो उन्होंने खुद को किनारे कर लिया। वर्ष 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ से विधायक चुने गए मंत्री बने और 2022 के विधानसभा चुनाव में बृजेश पाठक को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया।

उत्तराखंड - विजय बहुगुणा/तीरथ सिंह रावत

इसी तरह से उत्तराखंड में विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत दोनों पूर्व में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहे। दोनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। जब बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला तो बीजेपी ने दूसरी विचारधारा का होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर सियासी संदेश दिया। इसलिए बीजेपी के नेता कहते है कि हमारे यहां दूसरी राजनीतिक पार्टियों से आने वाले नेताओं को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना हमारी मूल विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं को। बीजेपी पूर्वात्तर से लेकर दक्षिण भारत तक दूसरे दलों से आए नेताओं को केंद्र में और राज्यों के मुख्यमंत्री बनाकर सियासी संदेश देने का काम रही है।

गर्मी में नहीं होगी पेयजल किल्लत...

ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी प्राथमिकता

भजनलाल सरकार का वॉटर एक्शन प्लान, अब ग्रामीण राजस्थान की बुझेगी प्यास

● लोक टुडे

जयपुर। राजस्थान में पारा चढ़ने के साथ ही पेयजल संकट की आहट को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता को धरातल पर उतार रही है। इसी कड़ी में प्रदेशभर में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसने ग्रामीण इलाकों में बंद पड़े जल स्त्रोतों में फिर से जान फूंक दी है।

गांव-गांव पहुंचे कलक्टर से तहसीलदार :

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद राजस्थान के सभी जिलों में जिला कलक्टर, एसडीएम और जलदाय विभाग के अभियंताओं ने दफ्तर छोड़कर गांवों का रुख किया। दो दिनों के भीतर कुल 2677 कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जल जीवन मिशन (छुछ्सरू) के 407, अमृत योजना के 80 और ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी के 77 महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति जांची गई।

अमृत और जल जीवन मिशन को मिली नई गति :

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की एक-एक बूंद कीमती है। अभियान के दौरान जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइनों की गुणवत्ता की भी जांच की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के मौसम में किसी भी गांव या ढाणी में टैंकरों पर निर्भरता कम की जाए और पाइपलाइन के जरिए नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो।

2775 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण

यह अभियान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तकनीकी टीमों ने मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। जलदाय विभाग की करीब 450 टीमों ने पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर कार्य किया। लंबे समय से खराब पड़े 1535 हैण्डपम्पों की मरम्मत कर उन्हें दोबारा चालू किया गया। पाइपलाइनों में रिसाव के कारण हो रही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए 911 स्थानों पर लीकेज दुरुस्त किए गए। पानी की टंकियों और वितरण केंद्रों पर 329 अन्य तकनीकी सुधार कार्य भी संपन्न किए गए।

ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी, सूखे हलक नहीं रहेंगे प्यासे :

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी कार्यों को प्राथमिकता दी है। जहाँ जल स्रोत सूख गए हैं, वहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाओं का सघन निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री के इस विजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गर्मी की तपिश बढ़ने से पहले ही बुनियादी ढांचा इतना मजबूत हो जाए कि लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों पैदल न चलना पड़े।

सरकारी स्कूलों में अब पासबुक से पढ़ा सकेंगे टीचर: शिक्षा विभाग ने 9 साल बाद अपना आदेश वापस लिया

बीकानेर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षक अब पासबुक से पढ़ाई करवा सकेंगे। सरकारी स्कूलों में पासबुक के उपयोग पर लगी रोक हटा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 9 साल पुराने आदेश में आगे अपील नहीं करने का फैसला लिया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. रामगोपाल शर्मा ने सोमवार (20 अप्रैल) को आदेश जारी किया, जिसमें पूर्व में जारी प्रतिबंध लगाने के 2 आदेशों को वापस(प्रत्याहरित) लेने का आदेश दिया गया।

9 साल पहले लगाई थी रोक

13 मार्च 2018 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संयुक्त रूप से आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों में पासबुक के उपयोग पर रोक लगा दी थी। आदेश में कहा गया था कि पासबुक के कारण छात्र मूल अध्ययन नहीं कर पाते और रटंत प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि यदि किसी छात्र या शिक्षक के पास पासबुक पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद 6 नवंबर 2023 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इसी आदेश को दोबारा जारी करते हुए पासबुक के उपयोग पर प्रतिबंध को फिर से लागू कर दिया था।

पासबुक पब्लिशर की अपील पर कोर्ट ने रोक लगाई

शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ प्राइवेट पब्लिशर 'संजीव पासबुक' ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आदेश को गलत बताते हुए चुनौती दी। मामले की सुनवाई के दौरान 12 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने इस आदेश पर रोक लगा दी।

सरकार ने आगे अपील नहीं करने का फैसला लिया

हाईकोर्ट के स्टे के बाद शिक्षा विभाग के पास अपील करने का विकल्प था, लेकिन सरकार ने आगे अपील नहीं करने का निर्णय लिया। 17 मार्च 2026 को संयुक्त विधि परामर्शी ऋतु शर्मा ने आदेश जारी कर पासबुक पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने के निर्देश दिए।

चारधाम यात्रा को लेकर चिकित्सा विभाग ने जारी की हैल्थ एडवाइजरी

● लोक टुडे

जयपुर। प्रदेश से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हैल्थ एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यात्रा के दौरान आवश्यक तैयारी, जरूरी वस्तुएं साथ में रखने एवं स्वास्थ्य संबंधी बिन्दुओं को शामिल किया गया है। निदेशक जन-स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित तीर्थ स्थानों में यात्री का स्वास्थ्य अत्यधिक ठण्ड, कम आर्द्रता, अत्यधिक अल्ट्रा वॉइलेट रेडिएशन, कम हवा का दबाव और कम ऑक्सीजन की मात्रा से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सभी सुगम एवं सुरक्षित यात्रा हेतु दिशा - निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यात्री अपनी यात्रा की योजना कम से कम 7 दिनों के लिए बनाएं, वातावरण के अनुरूप ढ़लने के लिए समय दें।

ट्रेक के हर एक घंटे बाद या ऑटोमोबाइल चढ़ाई के हर 2 घंटे बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। रोजाना 5-10 मिनट के लिए श्वास व्यायाम का अभ्यास एवं रोजाना 20-30 मिनट टहलना चाहिए। डॉ. शर्मा ने बताया कि वृद्धजन या हृदय रोग, अस्थमा, उच्च रक्तचाप या मधुमेह से ग्रसित रोगी फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं। साथ ही, गर्म कपड़े एवं बारिश से बचाव के लिए रेनकोट, छाता आदि साथ में लें। स्वास्थ्य जांच उपकरण पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर भी साथ रखें। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मधुमेह रोग वाले यात्री सभी जरूरी दवा, परीक्षण उपकरण और चिकित्सक का संपर्क नंबर साथ रखें। निदेशक जन-स्वास्थ्य ने बताया कि यात्रा के दौरान शराब, कैफीनयुक्त ड्रिंक्स, नींद की गोलियां और शक्तिशाली दर्द निवारक दवाओं का सेवन न करें, धूम्रपान से भी बचें। यात्रा के दौरान कम से कम दो लीटर तरल पदार्थ पिएं और भरपूर पोष्टिक आहार लें। कृपया अपनी यात्रा से पहले मौसम रिपोर्ट की जांच करें। उन्होंने बताया कि अगर डॉक्टर यात्रा न करने की सलाह देते हैं, तो यात्रा न करें। उत्तराखंड में चिकित्सा विभाग के सहायक निदेशक डॉ. अमित शुक्ला ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर तत्काल मदद प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी भी यात्री को सांस की तकलीफ (बात करने में कठिनाई), लगातार खांसी, चक्कर आना, भटकाव (चलने में कठिनाई), उल्टी, शरीर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नता जैसे लक्षण दिखाई दें तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र या टोल फ्री नंबर की मदद अवश्य लें। उन्होंने बताया कि वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मधुमेह या अधिक मोटापे से ग्रस्त यात्री चिकित्सा इकाइ?यों पर संपर्क करें और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। इसके अतिरिक्त कोई भी स्वास्थ्य सम्बंधित आपातकालीन घटना होने पर 104 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

रिफाइनरी में आग की जांच होनी चाहिए: रिफाइनरी पहले से लेट थी, अब 6 से 12 महीने और देरी हो जाएगी: डोटासरा

सीकर। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री रो रहा था, तब हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ईरान-इजरायल विवाद के समय भी प्रधानमंत्री नहीं रोए थे, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री आंसू बहा रहे थे। डोटासरा मंगलवार को सीकर के सांगलिया में कोजाराम सेवदा द्वारा अपने माता-पिता की स्मृति में भूमिदान देकर बनवाए गए पशु चिकित्सा उपकेंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए।

महिला आरक्षण बिल पर तीखा प्रहार

डोटासरा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तो 2022-23 में सितंबर माह में लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका था। गजट नोटिफिकेशन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन तीन साल तक नोटिफिकेशन नहीं किया गया। आखिरकार 15 अप्रैल 2026 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने बिल पास करवाते समय शर्त रखी थी कि पहले 2026 की जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और 2029 से कानून लागू होगा। लेकिन अब 2026 से पहले जनगणना करवाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर चाहें तो अभी जनगणना करवा लें और 2029 में महिला आरक्षण लागू कर दें। डीलिमिटेशन के लिए दो-तिहाई बहुमत से संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। वे यही संशोधन करवाकर सारे अधिकार अपने पास लेना चाहते थे, ताकि केवल बहुमत के बूते मनमाने ढंग से परिसीमन कर पूरे देश का भूगोल बदल सकें और भाजपा को हमेशा के लिए केंद्र में बनाए रख सकें। लेकिन अब उनका यह षड्यंत्र फेल हो गया है, इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। जनता सब जानती है। डोटासरा ने कहा, हमें शर्म आ रही थी कि हमारा प्रधानमंत्री रो रहा है। ईरान-इजरायल में भी ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि महिलाएं इनको माफ करेंगी। आप बताएं क्यों नहीं करेंगी जबकि हमने तो 2010 में ही राज्यसभा में बिल पारित करवा दिया था। महिला और ओबीसी आरक्षण कांग्रेस ने पंचायतीराज और निकाय में दे दिया। अब जब इनकी बारी आई और हमने समर्थन दे दिया और महिला आरक्षण पास हो गया तो उसके बाद लागू करना तो इनका काम है,विपक्ष का काम थोड़ी है। यह तो अपनी मनमर्जी का खेल करना चाह रहे थे। अब जनगणना करवाकर 2029 में महिला आरक्षण के कानून को लागू करवाना चाहिए।

राजस्थान की छतों पर उतरी सौर क्रांतिः 2417 मेगावाट क्षमता के साथ देश में मिला तीसरा स्थान

हर दिन लगभग 700 नए उपभोक्ता अपना रहे सोलर, 1.44 लाख उपभोक्ताओं का बिजली उपभोग बिल हुआ शून्य

● लोक टुडे

जयपुर। राज्य में सौर ऊर्जा के प्रति विद्युत उपभोक्ताओं का रूझान तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश में अब तक घरेलू, अघरेलू तथा औद्योगिक श्रेणी में कुल 2,45,317 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इससे 1,43,965 उपभोक्ताओं का बिजली उपभोग बिल शून्य हो गया है। छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर विद्युत उपभोक्ता ऊर्जा आत्मनिर्भर बन रहे हैं और देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। कुल रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। जिसकी कुल क्षमता 2090 मेगावाट है। गुजरात 6,882 मेगावाट क्षमता के साथ प्रथम, महाराष्ट्र 5,442 मेगावाट क्षमता के साथ द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में लगभग 32 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने 10 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के रूफ टॉप सोलर स्थापित किए हैं।

पीएम सूर्यघर में लगे 1.77 लाख संयंत्र

पीएम सूर्यघर योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक 686 मेगावाट क्षमता के 1 लाख 77 हजार 468 रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। प्रतिदिन औसतन 675 से 700 नए उपभोक्ता सौर ऊर्जा से जुड रहे हैं। विगत मार्च माह में कुल 20,343 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। यह किसी एक माह में स्थापित रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। मार्च माह की 23 तारीख को एक ही दिन में 910 सौर ऊर्जा संयंत्र लगे। यह किसी भी एक दिन में लगे सोलर की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले इसी जनवरी माह में 20,853 तथा फरवरी माह में 16,957 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए थे। पीएम सूर्यघर योजना में गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद राजस्थान देश में पांचवें स्थान पर है।

150 यूनिट योजना में 13 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को सब्सिडी :

प्रतिमाह 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना के अन्तर्गत रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने पर 13141 उपभोक्ताओं को जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा 17 हजार रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा चुकी है। इस योजना में अब तक 23,273 उपभोक्ताओं ने सोलर संयंत्र लगा लिए हैं। इस प्रकार 150 यूनिट योजना में करीब 22 करोड 33 लाख रूपए की सब्सिडी उपभोक्ताओं को मिल चुकी है। दिसम्बर, 2025 से इस योजना में सब्सिडी वितरण की शुरूआत हुई थी। इस प्रकार प्रदेश में रूफ टॉप सोलर लगाने पर उपभोक्ताओं को पीएम सूर्यघर योजना में अधिकतम 78 हजार रूपए तथा 150 यूनिट योजना में 17 हजार रूपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है।

बैंकों से मिल रहा आसान ऋण :

पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए बैंकों से लगभग 5.75 प्रतिशत की आसान ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी मिल रही है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदेश में 62,236, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा 9,292, राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा 8,169, कैनरा बैंक द्वारा 1,866 तथा अन्य बैंकों द्वारा 16,666 विद्युत उपभोक्ताओं को रूफ टॉप लगाने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

प्रक्रियाओं को बनाया सुगम :

जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों ने रूफ टॉप इंस्टॉलेशन से जुडी प्रक्रियाओं को सुगमता प्रदान की है। इसके अन्तर्गत कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिमाह रूफ टॉप सोलर चैंपियन अवॉर्ड प्रारंभ किया गया। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर इंस्टालेशन की राह में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। आवेदन करते किसी प्रकार के शुल्क, बडी हुई सिक्योरिटी राशि, मीटर परीक्षण शुल्क तथा नेट मीटरिंग एग्रीमेंट आदि से उपभोक्ताओं को छूट दी गई। सभी तरह के चार्जेज प्लांट स्थापित होने के बाद बिजली बिल के माध्यम से लेने, पीएम सूर्यघर योजना में कनेक्शन के आवेदनों के लिए अलग से प्राथमिकता रखने, बैंकों से उपभोक्ताओं को आसानी से ऋण मिल सके, इसके लिए लगातार बैंकर्स के साथ संवाद किया गया। विद्युत सब डिविजन स्तर तक लगातार कैम्प आयोजित कर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है।

प्रत्येक 6 माह में ही दोगुना इंस्टालेशन

पीएम सूर्यघर योजना में प्रत्येक छह माह में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या दो से डाई गुना तक बड रही है। फरवरी, 2024 में इस योजना की शुरूआत हुई। इसके प्रथम शुरूआती 6 महीनों में मात्र 7,694 उपभोक्ताओं ने ही रूफ टॉप सोलर लगाए थे। इसके बाद प्रत्येक 6 माह के अन्तराल में क्रमशः 19,45, 39,311 तथा 68,450 उपभोक्ताओं ने रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं। इस वर्ष के शुरूआती 3 माह में कुल 58,153 उपभोक्ता सौर संयंत्र इंस्टॉल करा चुके हैं। इसे देखते हुए उम्मीद है कि इस साल के प्रथम 6 माह में रूफ टॉप संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1 लाख से अधिक पहुंच जाएगी।

1185 करोड की सब्सिडी हस्तांतरित

पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप संयंत्र लगाने के करीब एक से डेड माह के भीतर ही 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी राशि उपभोक्ता के खाते में हस्तांतरित हो जाती है। अब तक 1 लाख 52 हजार 350 उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भारत सरकार से 1185 करोड रूपए की सब्सिडी राशि हस्तांतरित हो चुकी है। इस प्रकार करीब पीएम सूर्यघर के 85 प्रतिशत लाभार्थियों को सब्सिडी मिल चुकी है।

लगभग 1900 वेंडर्स हैं पोर्टल पर रजिस्टर्ड :

पीएम सूर्यघर योजना को घर-घर तक पहुंचाने में वेंडर्स भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रदेश में पीएम सूर्यघर नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले वेंडर्स की संख्या बडकर 1896 तक पहुंच गई है। योजना की शुरूआत में 762 वेंडर्स ही सेवाएं दे रहे थे।

ग्राम पंचायत स्तर पर होंगे कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम, महिला किसान को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने का प्रयास

● लोक टुडे

जयपुर। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं खेती किसानी से लेकर पशुपालन, रोपाई, निराई, गुढाई, कटाई और भंडारण तक लगभग हर कार्य में सक्रिय योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में महिलाओं की कृषि में भागीदारी बढ़ाने और नवीन कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर महिला प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा। पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में 11 हजार 019 महिला कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3 लाख 30 हजार 570 महिला कृषकों को लाभान्वित किया गया है। आयुक्त कृषि नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रशिक्षण में लघु-सीमान्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों (स्।त्र) की महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ग्राम स्तर पर महिला कृषक नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी ले कर उत्पादन में वृद्धि कर सके।

ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन :

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल का चयन उस गाँव से किया जाएगा, जहाँ पिछले दो वर्षों में इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं हुआ हो, ताकि महिला कृषकों में प्रशिक्षण की नवीनता बनी रहे और पुनरावृत्ति न हो। कृषि विभाग के आयुक्त ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में फसलों के बीज उत्पादन तकनीक, मृदा एवं जल परीक्षण का महत्व, नमूनों का संकलन एवं उपयोग, सन्तुलित उर्वरक प्रबंधन, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक खेती व जैविक खाद बनाने की विधियों पर गहन चर्चा एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण, शुष्क खेती एवं फसलों की क्रांतिक अवस्था पर समयानुसार सिंचाई, बून्द-बून्द (ड्रिप), फव्वारा सिंचाई एवं पाईप-लाइन, डिग्गी निर्माण से पानी का कुशल उपयोग; खरपतवार व कीटों का वैज्ञानिक नियंत्रण, उन्नत फसल किस्में, बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने की विधियाँ, जैविक तथा रासायनिक खेती में संतुलन बनाने की तकनीकें का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भागीदारों को विभागीय योजनाओं के लाभ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी।

ज्ञान परीक्षण व प्रशिक्षण उपरान्त रिपोर्टिंग :

प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक महिला कृषक की ज्ञानार्जन परख के लिए वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण-परीक्षण आयोजित किया जाएगा। परीक्षण के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली महिलाओं को किसान टार्च, लोहे की बाल्टी, तश्ला, डोल्ची, खाद-बीज या अन्य उपयोगी कृषि सामग्री जैसे पुरस्कार दिए जाएँगे। प्रशिक्षण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, महिला बाल विकास विभाग, राजीव गांधी सेवा केन्द्र (राजीविका) के बीपीएम, ग्राम स्तरीय कृषि/पशु सखी एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही प्रगतिशील कृषकों को आमंत्रित कर उनके अनुभवों को मंच पर रखा जाएगा, जिससे अन्य कृषक महिलाएँ व्यावहारिक ज्ञान ले सकें।

महिला कृषकों की आत्मनिर्भरता बढ़ाना :

नरेश कुमार ने बताया इस कृषक महिला प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य न केवल तकनीकी ज्ञान देना है, बल्कि महिला कृषकों को विभागीय योजनाओं, अनुदान प्रक्रिया तथा वैज्ञानिक खेती से जोड़कर आर्थिक स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा देना है। राज्य सरकार द्वारा सतत खेती, जल-संरक्षण और जैविक खेती के माध्यम से महिला कृषकों को खाद्य-सुरक्षा एवं जलवायु अनुकूल खेती में नया नेतृत्व-स्तर बनाने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

पंच गौरव संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए जनभागीदारी आवश्यक: कलेक्टर

● लोक टुडे

जयपुर। जयपुर जिले में चिन्हित पंच-गौरव के संरक्षण, संवर्धन एवं समग्र विकास को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि पंच-गौरव केवल धरोहर संरक्षण की योजना नहीं, बल्कि यह स्थानीय पहचान, सांस्कृतिक गौरव एवं भावी पीढ़ी को अपनी विरासत से जोडने का सशक्त माध्यम है। इसके संरक्षण एवं विकास के लिए प्रशासन, शिक्षा संस्थानों और समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने पंच-गौरव की महत्ता, उपयोगिता एवं आवश्यकता को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से सभी राजकीय कार्यालयों, सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों में पंच-गौरव का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं ताकि युवाओं, विद्यार्थियों एवं आमजन में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक धरोहरों के प्रति जागरूकता एवं संरक्षण की भावना विकसित हो।

जिला कलक्टर ने एक जिला एक खेल कबड्डी के विकास के लिए जिला खेल अधिकारी को जिले के गाँव-गाँव में खिलाडी एवं कोच तैयार करने के, ब्लॉक स्तर पर कबड्डी खेल को बडावा देने के लिए इंडोर स्टेडियम बनवाने के निर्देश दिये। उन्होंने विश्व पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखने वाले जयपुर के आमेर किले के विकास एवं पर्यटकों के लिए बेहतरीन सुविधाएँ सुनिश्चित करने और आमेर किले में बेहतर साफ-सफाई, शौचालय निर्माण, पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाने, साइनेज लगवाने के साथ-साथ रास्ते में आने वाली झाडियों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने एक जिला एक उपज आँवला के विकास के लिए आमजन को इसके आयुर्वेदिक गुणों की जानकारी के संबंध में अवगत करवाने के लिए संबंधित विभाग को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा है।

वहीं उन्होंने एक जिला एक वनस्पति लिसोडा के पौधों के वितरण सहित लिसोडा के बहुउपयोग के संबंध में आमजन को प्रचार-प्रसार के माध्यम से अवगत करवाने के लिए भी उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने एक जिला एक उत्पाद जैम्स एंड ज्वैलरी के विकास के लिए वर्कशॉप, सेमिनार, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक भ्रमण जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। मुख्य आयोजन अधिकारी डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि कार्यक्रमों, मेलों एवं सार्वजनिक आयोजनों में पंच-गौरव से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगें जहां आमजन को पंच-गौरव स्थलों की जानकारी, उनके संरक्षण की आवश्यकता तथा उनसे जुडी सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम विनीता सिंह, वी. केतन कुमार, सांख्यिकी विभाग के संयुक्त निदेशक बाबुलाल मीणा, उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक हरलाल बिजारनियां, जिला खेल अधिकारी मान सिंह एवं पर्यटन अधिकारी बाबूलाल मीणा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम को पारित होने से रोका : डॉ राधा मोहनदास अग्रवाल

भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रदेश कार्यालय में की प्रेसवार्ता

रूपनारायण सांवरिया ● लोक टुडे

जयपुर। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय समाज में महिलाओं ने सदैव परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, हाड़ी रानी, रानी कर्णावती, रानी पद्मावती, पन्ना धाय तथा अमृता देवी बिश्नोई का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं का योगदान ऐतिहासिक रूप से प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद जब नरेंद्र मोदी महिलाओं को शीघ्र आरक्षण दिलाना चाहते थे, तब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इसमें बाधाएं उत्पन्न कीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से षडयंत्र रचते हुए संशोधन अधिनियम को पारित नहीं होने दिया। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री इस विरोध से न तो हतोत्साहित हुए हैं और न ही उनके आत्मविश्वास में कोई कमी आई है। भाजपा महिलाओं के आरक्षण को एक सैद्धांतिक विषय मानती है और यह विश्वास रखती है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना देश के विकास और परिपक्व राजनीति की कल्पना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द से जल्द महिला आरक्षण को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भाजपा विरोधी

दलों के इस रुख को महिला विरोधी बताते हुए उसकी निंदा की। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ अग्रवाल ने कहा कि महिला आरक्षण के विरोध में विपक्ष का इस तरह खुलकर सामने आना अप्रत्याशित है। महिला आरक्षण के विरोध में विपक्ष इतने नंगे होकर सामने आ जाएंगे, इसका किसी को विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में विपक्ष ने मजबूरी में मन मसोसकर इस विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन अब जब चुनाव दूर हैं, तो उन्हें लगता है कि जनता की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसी कारण वे दक्षिण भारत की सीटों में कमी जैसे विभिन्न बहानों के आधार पर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं जागरूक और सजग हैं तथा वे विपक्ष का वास्तविक चेहरा समझ चुकी हैं। समय आने पर महिलाएं इसका उचित जवाब देंगी और अब विपक्ष पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष को यह भय है कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद भाजपा की बाढ़ आ जाएगी। इसे व्यापक जनसमर्थन मिलेगा। 'इंडी ठगबंधन' के दल एकजुट नहीं रह सकते और लगातार आपसी संघर्ष में उलझे रहते हैं। ये संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए गठबंधन करते है,जबकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से अलग हैं, वहीं केरल में सीपीएम और कांग्रेस आमने-सामने हैं। इससे स्पष्ट है कि यह कोई वैचारिक गठबंधन नहीं, बल्कि केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए बना अस्थायी समूह है। डॉ. अग्रवाल ने विपक्षी दलों को परिवारवादी बताते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियां परिवारवाद पर आधारित हैं और इनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। उन्होंने कहा कि अब इन दलों को यह आभास होने लगा है कि देश की जनता परिवारवाद की राजनीति को नकार रही है और भविष्य में इनका राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि देश में पूर्व की व्यवस्थाओं में महिलाओं को पीछे धकेला गया, लेकिन भाजपा ने हमेशा महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का कार्य किया है। उन्होंने वसुंधरा राजे के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि वे महिला सशक्तिकरण की जीवंत प्रतीक हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार के षडयंत्रों के लिए जाने जाते है। वसुंधरा राजे ने इस पर खुलकर अपना पक्ष रखा है और राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसमें जिसने भी चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजस्थान में पहले एक प्रभावी महिला मुख्यमंत्री दी, अब प्रभावी महिला को उपमुख्यमंत्री बनाया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बहन मायावती को तीन बार समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री बनाया, तो दिल्ली में आज और पहले भी महिला मुख्यमंत्री दी। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि भाजपा का सिद्धांत स्पष्ट है महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए और पार्टी इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

नमक उत्पादकों की पीड़ा: रिफाइनरी तो तैयार, हम अब भी जमीन के मोहताज

रिफाइनरी से प्रभावित 198 नमक की खानों के लिए 841 बीघा भूमि चिन्हित, आवंटन का इंतजार

600 साल से नमक का उत्पादन करता है खारवाल समाज, 13 सालों से झेल रहा बेरोजगारी का दंश

रिपोर्ट:
मनोहरसिंह खोखर

जयपुर। रिफाइनरी में आग की घटना से लोकार्पण का कार्यक्रम अब स्थगित हो गया है, लेकिन अब नहीं तो आने वाले समय में यह भी हो जायेगा, लेकिन रिफाइनरी से प्रभावित हुई 198 खदानों को भी जमीन आवंटित नहीं हुई है। इसका दंश खारवाल समाज पिछले 13 सालों से झेल रहा है। ऐसे में करीब 8 साल से प्रभावित खानों के मालिक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार अपने वादों से मुखर गई है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उनको थोड़ी उम्मीद जगी थीं कि शायद ज्ञापन के मार्फत ही उनकी आवाज पीएम मोदी तक पहुंच जाएगी, मगर रिफाइनरी में आग की घटना ने उन उम्मीदों को भी धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उल्लेखनीय है की पचपदरा साल्ट व सांभरा की नमक खदानें करीब 600 साल से देश व विदेश तक लोगों के लजीज खाने में स्वाद का रस घोल रही है। इन्हें लोगों की थाली तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता आ रहा है यहां का नमक उत्पादक खारवाल समाज। पहले सरकार की उपेक्षा के चलते यहां का नमक कारोबार गर्त में चला गया और रही-सही कसर रिफाइनरी का कार्य शुरू होते ही पूरी कर दी।

नमक की खान

पारसमल खारवाल

जैसलसिंह खारवाल

ब्रिटिश काल से नमक का उत्पादन

पचपदरा के रण क्षेत्र में 32.34 वर्ग मील में नमक उत्पादन की खानें फैली हुई है। करीब 600 साल से खारवाल समाज के लोग नमक उत्पादन कर अपनी आजीविका चला रहे है। ब्रिटिश शासन काल में मारवा? स्टेट में प्रथम रेल सेवा शुरु कर नमक को बाहरी राज्यों में भिजवाने पर स्थानीय लोगों को अच्छा रोजगार मिलने लगा। इस पर खानों की संख्या बढतर 1280 तक पहुंच गई, लेकिन वर्ष 1960 से नमक की खानें सरकार के अधीन आने से इसकी दुर्दशा का दौर शुरू हो गया। सरकार के सड़क, पानी, बिजली जैसी मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने व बाहरी राज्यों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं देने से धीरे-धीरे नमक उत्पादन का कार्य मंदी के गर्द में समाता गया। हालाँकि तत्कालीन भैरोसिंह शेखावत की सरकार ने उनको राहत प्रदान करते हुए खदानों को मालिक के अधीन करते हुए सरकार से फ्री हैंड कर दिया था।

परंपरागत नमक उद्योग से ही पचपदरा की पहचान

ब्रिटिशकाल में मारवाड़ क्षेत्र में एकमात्र नमक उद्योग ही विकसित था। स्थानीय नमक की मांग पर सांभरा में ब्रिटिश सरकार ने गेस्ट हाऊस, ट्रेजरी व चौकियां बना रखी थी। जगह-जगह बनी चौकियों में गार्ड नमक की खानों की निगरानी रखते थे। तत्कालीन सरकार नमक उत्पादकों से पेशगी वसूला करते थे। इसके बाद यहां से उत्पादित नमक को असम, बंगाल सहित राज्यों व विदेशों में भेजते थे। यहां से मिलने वाली राशि ट्रेजरी से नमक उत्पादकों को दी जाती थी।

198 खदानें हुई थीं जमीदोंज

पचपदरा के सांभरा इलाके में रिफाइनरी का कार्य शुरु होने पर 198 नमक की खानों को पाटा गया था। इस दौरान लवण उत्पादक समाज ने रोजगार छीनने को लेकर कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। इसे देखते हुए सरकार ने रिफाइनरी में प्रभावित खानों की रिपोर्ट तैयार कर उत्पादकों को दूसरी जगह भूमि आवंटित कर खदानें तैयार कर देने के निर्देश दिए थे। जिस पर 19 फरवरी 2018 को तत्कालीन कलक्टर डॉ. शिवप्रसाद एम. नकाते की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम ने खदानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद खानों को शिफ्ट करने को लेकर 841 बीघा भूमि चिह्नित की गई, लेकिन अभी तक जमीन आवंटित नहीं हो पाई है। करीब तीन साल पहले सरकार ने कलेक्टर को जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर कार्यालय में फाइल अटकी रहने से इन्हें खानें आवंटित नहीं हो पा रही है।

बजट स्वीकृत, लेकिन ऊंट में मुंह में जीरा

नमक उत्पादकों का कहना है कि सरकार की ओर भूमि आवंटित कर खदानें तैयार करवाने के लिए बजट तो स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन बाजार दर से काम होने के कारण खदानें तैयार नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि सरकार अपने स्तर पर कार्यकारी एजेंसी से टेंडर करवाकर खदानें तैयार करवाए, सरकार के तय बजट से खुद के स्तर पर खदानें तैयार करवाना ऊंट के मुंह में जीरा समान है।

13 साल से बेरोजगारी का दंश

वर्ष 2013-14 में तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। इस दरम्यान रिफाइनरी के लिए 12034.10 बीघा जमीन हस्तांतरित की गई थी। इसमें 198 खदानें जो रिफाइनरी की परिधि में आ रही थी, इन्हें जमींदोज किया गया था। इन खदानों के मालिकों ने रोजगार छीन जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तब इन्हें दूसरी जगह भूमि आवंटित कर खदानें तैयार करवाकर देने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक जमीन आवंटित नहीं होने से खदानें तैयार नहीं हो पाई है। ऐसे में सैकड़ों परिवार 13 साल से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। प्रभावित खदान मालिकों का कहना है कि सरकार 2013 से अब तक उन्हें हुई आय की क्षति का आंकलन कर मुआवजा दें, वहीं समय रहते खानें आवंटित की जाए, ताकि परंपरागत नमक की खानों को फिर से शुरु किया जा सके।

पहले चलती थी रेल, अब फिर प्रस्तावित :

नमक परिवहन के यहां पर रेल लाइन बिछाई गई थी, जहां से मालगाडियों में नमक का लदान कर ले जाया जाता था। रिफाइनरी का कार्य पूरा होने के बाद यहां पर 400 से अधिक बायो प्रोडक्ट के कारखाने खुलेंगे। ऐसे में सरकार परंपरागत लवण उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देकर कार्य शुरु करवाए तो यहां का नमक फिर से अपनी खोई साख हासिल कर सकेगा। बालोतरा और पचपदरा के बीच 11 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जिससे न केवल पेट्रोलियम बल्कि नमक के परिवहन में भी आसानी होगी।

600 साल पुरानी विरासत...

रिफाइनरी निर्माण के लिए अवाप्त की गई भूमि के कारण लगभग 198 नमक की खानें प्रभावित हुई थीं। राज्य सरकार ने इन प्रभावित नमक उत्पादकों (विशेषकर खारवाल समाज) के लिए लगभग 500 से 841 बीघा जमीन स्वीकृत की है ताकि वे फिर से नमक उत्पादन शुरू कर सकें। पचपदरा का नमक उद्योग करीब 600 साल पुराना है। रिफाइनरी आने से इस पारंपरिक उद्योग के खत्म होने का डर था, लेकिन जमीन चिन्हिकरण होने के बाद उनकी उम्मीद अब भी बरकरार है। रिफाइनरी के मुख्य क्षेत्र में आने वाली कई खदानें जमींदोज हो चुकी हैं।

अब बडे बदलाव की ओर पचपदरा....

रिफाइनरी पूरी तरह बन कर तैयार हो चुकी है। लोकार्पण भी 21 अप्रैल को हो जाता, मगर आग की घटना की वजह से वह टल गया। पचपदरा अब एक बडे औद्योगिक बदलाव की दहलीज पर खडा है। यहाँ देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल परियोजना बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित था। हालांकि, उद्घाटन से ठीक पहले आग लगने की घटना के कारण सुरक्षा कारणों से पीएम का दौरा स्थगित कर दिया गया है। लगभग 79,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली यह परियोजना राजस्थान के औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्र के लिए रेगिस्तान का रत्न साबित होगी। यह रिफाइनरी प्रति वर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता रखती है, जिससे न केवल ईंधन बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले पॉलिमर का भी उत्पादन होगा। यह परियोजना मारवाड़ क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

बुनियादी ढांचे में भी बदलाव

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: पचपदरा रिफाइनरी को जयपुर से जोड़ने के लिए लगभग 350-400 किलोमीटर लंबा जयपुर-पचपदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है।

कनेक्टिविटी: यह एक्सप्रेसवे जयपुर, अजमेर (किशनगढ़), पाली और जोधपुर से होकर गुजरेगा, जो लॉजिस्टिक परिवहन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।

रोजगार और अवसर: इस मेगा प्रोजेक्ट से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

कौशल विकास: रिफाइनरी के संचालन और डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल उद्योगों के आने से तकनीकी क्षेत्र में भी कौशल विकास के अवसर बढ़ेंगे।

सरकारी उपेक्षा का शिकार नमक उद्योग

सरकार की ओर से रिफाइनरी स्थापित करने के दौरान हमें जमीन के बदले जमीन देने का वादा किया गया था। उस बात को 13 साल हो गए है, लेकिन सरकार की अनदेखी अब उन पर भारी पड़ रही है। नमक उद्योग पर निर्भर हम लोग बेरोजगारी झेल रहे है। हालाँकि आग की घटना से रिफाइनरी का लोकार्पण टल गया। रिफाइनरी स्थापित होने से लेकर अब तक 13 बीत गए है, लेकिन हमें जमीन आवंटन नहीं की गई है।

- पारसमल खारवाल, अध्यक्ष, सांभरा आशापुरा नमक उत्पादन क्षेत्र विकास समिति पचपदरा।

रिफाइनरी शुरू होने के बाद सरकार को तो राजस्व मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमसे सरकार ने रोजी रोटी छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 13 सालों में रिफाइनरी पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है, मगर जमीन आवंटन का मामला अब भी फाइलों में दबा पड़ा है। अगर समय रहते जमीन आवंटन नहीं हुआ तो पूरा समाज बड़े आंदोलन का रूख करेगा।

- जैसलसिंह खारवाल, संरक्षक, सांभरा आशापुरा नमक उत्पादन क्षेत्र विकास समिति पचपदरा।

फैक्ट फाइल

- नमक उत्पादित क्षेत्र 32.34 वर्ग मील
- नमक की खानें बंटी है 4 सेक्टर में
- कुल खानें 1200 से अधिक
- रिफाइनरी से प्रभावित 198 खानें

भागवत बोले- विज्ञान और धर्म दोनों से नहीं मिली शांति:राजा से विज्ञान तक सब मॉडल फेल

दुनिया अब भारत के ज्ञान से उम्मीद लगा रही

अगरतला। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि 2000 साल तक शासन, धर्म और विज्ञान के अलग-अलग प्रयोगों के बाद अब दुनिया भटक गई है और भारत के ज्ञान की ओर देख रही है। उन्होंने यह बात त्रिपुरा के मोहनपुर में धार्मिक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि कुछ 'दुष्ट शक्तियां' इस बात से चिंतित हैं कि अगर भारत अपनी सदियों पुरानी सभ्यतागत ताकत के सहारे आगे बढ़ा, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। भागवत मां सौंदर्य चिन्मयी मंदिर के प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के लोगों के बीच धार्मिक और भाषाई आधार पर फूट डालने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता में निहित है।

ज्ञान और शक्ति, दोनों अर्जित करें

भागवत ने कहा, जिन देशों का इतिहास 4,000 या 5,000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, वहां एक धर्म और एक भाषा हो सकती है, लेकिन भारत पूरी तरह से अलग है। इसका इतिहास, परंपरा और संस्कृति बहुत पुरानी और समृद्ध है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने और फूट डालने की कोशिशों को नाकाम करने का आग्रह किया। कहा, हालात चाहे जैसे भी हों, डरने की कोई ज़रूरत

नहीं है। मौजूदा विश्व व्यवस्था में, अकसर शक्ति ही सही को दबा देती है। अगर आपके पास शक्ति है, तो आपकी ताकत साबित हो जाएगी; अगर आप सही रास्ते पर भी हैं, लेकिन आपके पास शक्ति नहीं है, तो कोई आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए, ज्ञान और शक्ति, दोनों अर्जित करें। भागवत ने कहा कि मंदिर केवल पूजा-पाठ के स्थान नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वे सामाजिक जीवन और ज्ञानोदय के केंद्र रहे हैं।

विकास जितना बढ़ रहा है, पर्यावरण उतना ही नष्ट हो रहा

भागवत ने कहा कि पहले सत्ता राजा को दी गई, लेकिन बाद में राजा ही जनता का शोषण करने लगा। इसके बाद लोगों ने भगवान को सर्वोच्च मानकर धर्म बनाए, लेकिन इससे भी खून-खराबा नहीं रुका। विज्ञान के दौर में भी मानव की समस्याएं खत्म नहीं हुईं। लोगों ने कहा कि हम वैज्ञानिक हैं, जब तक भगवान लैब में नहीं दिखेगा, हम नहीं मानेंगे। इसके बाद विज्ञान का दौर आया। कई सुविधाएं और आराम मिले, लेकिन संतोष नहीं आया। आज भी दुनिया में दुख है, परिवार टूट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। युद्ध शुरू होते हैं तो रुकते नहीं। विकास जितना बढ़ रहा है, पर्यावरण उतना ही नष्ट हो रहा है। अब 2000 साल के इन प्रयोगों के बाद दुनिया भटक रही है और भारत के ज्ञान की ओर उम्मीद से देख रही है। उन्होंने इसे भारत का कर्तव्य बताया और कहा कि यही भारत के जीवन का उद्देश्य है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रिक, प्रकाशन, संपादक - नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, हटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड, जयपुर - 302006 से मुद्रिक एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झेलना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) प्रकाशित प्रबंध संपादक - पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)